



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]  
No. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2010/माघ 26, 1931

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2010/MAGHA 26, 1931

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुडगाँव, 11 फरवरी, 2010

सं. जेईआरसी-8/2009.—संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

## 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शीयों की नियुक्ति) विनियम, 2010 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## 2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, —
  - (क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
  - (ख) “आयोग” से गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
  - (ग) “परामर्शी” में कोई व्यष्टिक, जो आयोग के नियोजन में नहीं है, फर्म, निकाय या व्यक्तियों का ऐसा संगम सम्मिलित है जिनके पास कोई विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या कुशलता है;
  - (घ) “सचिव” से आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

(1)

- (2) इन विनियमों में आने वाले शब्दों या अभिव्यक्तियों किन्तु जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संव्यवहार) विनियम, 2009 में परिभाषित है; का वही अर्थ होगा जो अधिनियम या उक्त कारबार संव्यवहार विनियमों में है।

### 3. कार्यक्षेत्र

आयोग समय-समय पर, ऐसे विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए परामर्शियों की नियुक्ति कर सकेगा जिसको आयोग के कर्मचारिवृद्ध न कर सकें या जहां कार्य की प्रकृति विशेष और समयबद्ध हो या जहां आयोग क्वालिटी, लागत, समय या किसी अन्य प्रतिमान के अनुसार कार्य को साधक या अधिक प्रभावोत्पादक या दक्ष पद्धति से पूरा किए जाने के लिए परामर्श की नियुक्ति करना आवश्यक समझता है।

- (1) परामर्शियों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें प्रत्येक मामले में अलग होंगी तथा परामर्शी कार्य देने से पूर्व परामर्शी तथा आयोग के बीच तय की जाएंगी।
- (2) नियुक्ति की शर्तों में परामर्शी द्वारा असंभ किए जाने वाले कार्यों की सही प्रकृति, प्रत्येक कार्य तथा ऐसे विनिर्दिष्ट आउटपुट जिसे प्रत्येक कार्य के संबंध में परामर्शी द्वारा प्रदान किया जाना है, को पूरा करने के लिए अनुज्ञात समय को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

### 4. नियुक्ति की अवधि

परामर्शी की नियुक्ति न्यूनतम अवधि के लिए की जाएगी :

परंतु यह कि किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए परामर्शी की अनंतिम नियुक्ति की अवधि सामान्यतः दो वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि नियुक्ति की अवधि इस शर्त के अधीन रहते हुए बढ़ाई जाएगी कि किसी भी दशा में परामर्शी की निरंतर नियुक्ति की अधिकतम अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

### 5. परामर्शियों का प्रवर्गीकरण

परामर्शियों को (क) संस्थानिक परामर्शियों, तथा (ख) व्यष्टिक परामर्शियों, के रूप में प्रवर्गीकृत किया जाएगा।

### 6. संस्थानिक परामर्श

आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि उन परामर्शी सेवाओं को लेने की आवश्यकता है, जो उसकी राय में, फर्म, या किसी कंपनी या व्यक्ति-संगम या निकाय द्वारा प्रदान की गई सेवा से अधिक समुचित हो सकेगी, संस्थानिक परामर्शी की नियुक्ति कर सकेगा।

### 7. व्यष्टिक परामर्शी

व्यष्टिक परामर्शी की नियुक्ति ऐसे कार्य के लिए की जा सकेगी जिसके लिए कार्मिकों के टीम की आवश्यकता नहीं है, जहां व्यष्टिक के अनुभव और अहर्त्ताओं पर सर्वोच्च रूप से विचार किया जाता है तथा आयोग की यह राय है कि किसी ऐसे व्यष्टिक द्वारा परामर्शी सेवाएं अधिक दक्षता से दी जा सकती है, जिसके पास कार्य के लिए सुसंगत अर्हता तथा अनुभव है।

### 8. व्यष्टिक परामर्शियों का प्रवर्गीकरण

- (1) अनुभव के आधार पर, व्यष्टिक परामर्शियों को निम्नलिखित रूप में प्रवर्गीकृत किया जाएगा :

प्रवर्ग	नियुक्ति के क्षेत्र में न्यूनतम् अनुभव
सलाहकार	15 वर्ष
वरिष्ठ परामर्शी	10 वर्ष
परामर्शी	3 वर्ष

- (2) आयोग कार्य की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, न्यूनतम् शैक्षिक अर्हताएं तथा परामर्शी के विषय के क्षेत्र से संबंधित सुसंगत वृत्तिक अर्हताएं विहित कर सकेगा।
- (3) आयोग व्यष्टिक परामर्शी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे व्यक्ति की संपूर्ण विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, समुचित मामले में, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए शैक्षिक अर्हताओं को शिथिल कर सकेगा।

### 9. व्यष्टिक परामर्शियों की दशा में फीस तथा अन्य प्रभार

- (1) जहां आयोग अन्यथा निदेश न दे उसके सिवाय, व्यष्टिक परामर्शी की नियुक्ति साधारणतः अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर समेकित फीस पर की जाएगी :

परंतु यह कि आयोग, समय-समय पर, लिखित में आदेश द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस की दरों को पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा।

- (2) उप-विनियम (1) के अनुसार समेकित फीस के अतिरिक्त, व्यष्टिक परामर्शी की दशा में कोई संदाय नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि आयोग आकस्मिक प्रकृति के व्यय को सम्मिलित करने के लिए, परामर्शी को संदेय फीस के 10% से अनधिक अतिरिक्त रकम को अनुज्ञात कर सकेगा।

- (3) जहां परामर्शी ने आयोग के मुख्यालय से दूर यात्रा करने या इससे दूर स्थान पर ठहरने के लिए व्यय उपगत किया हो वहां आयोग समुचित श्रेणी में यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा जो केंद्रीय सरकार के समूह “क” अधिकारी को अनुज्ञात व्यय से कम न होगी तथा ऐसे दिनों के लिए, इन विनियमों के अधीन संदेय फीस तथा अन्य प्रभारों के अतिरिक्त अनुसूची में यथानिर्दिष्ट, दैनिक भत्ते का प्राधिकृत संदाय कर सकेगा जिसे आयोग समझे।

- (4) इन विनियमों के अधीन व्यष्टिक परामर्शियों को संदेय फीस तथा अन्य प्रभारों का संदाय परामर्शी के रूप में नियुक्त भूतपूर्व तथा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी किया जाएगा।
- (5) संस्थानिक परामर्शी की दशा में, व्यष्टिक परामर्शियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए दरों का उपयोग प्रस्ताव में परामर्शी समय के लिए आर्बांटित लागत की उपयुक्तता को अवधारित करने के लिए, व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किया जाएगा। परामर्शी समय की लागत के अतिरिक्त, टेलीफोन, फोटोकापीयर फैक्स खर्च आदि जैसे कार्यालय व्यय के मद्दे उपरिव्यय के लिए अनुज्ञेय रकम बातचीत के अधीन रहते हुए होगी तथा इन विनियमों के बारे में वार्तविक स्थिति पर व्यापक रूप से आधारित होगी। संस्थानिक परामर्शी की दशा में आकस्मिकता के लिए सीमा, कार्यालय खर्च के लिए उपरिव्यय के रूप में अनुज्ञात रकम के अतिरिक्त परामर्श समय के लिए संदेय फीस का 10% होगी।

#### 10. परामर्शी की नियुक्ति

- (1) आयोग का यह समाधान हो जाने पर कि किसी कार्य के लिए परामर्शी की सेवाएं लेने की आवश्यकता है तो वह सचिव को विस्तृत संदर्भ-निबंधन को तैयार करने या करने का निर्देश दे सकेगा।
- (2) आयोग या तो संयुक्त तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों या पृथक् तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों को आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकेगा।
- (3) आयोग तकनीकी बोली के लिए न्यूनतम अर्हक अंक विहित कर सकेगा।
- (4) सचिव किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए परामर्शी की नियुक्ति हेतु विस्तृत संदर्भ निबंधन तैयार करेगा या कराएगा तथा आयोग का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।
- (5) संदर्भ-निबंधन कार्य के उद्देश्य, लक्ष्य तथा परिधि को विनिर्दिष्ट करने तथा पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किए जाएंगे जिसमें विद्यमान सुसंगत अध्ययनों की सूची तथा उसके प्रस्ताव को तैयार करने में परामर्शी को सुकर बनाने के लिए बेसिक आंकड़े सम्मिलित होंगे :

परंतु यह कि संदर्भ-निबंधनों के कार्य को करने के लिए आवश्यक सेवाओं तथा सर्वेक्षणों की सूची तथा संदर्भ-निबंधन में सम्मिलित प्रत्येक कार्य से जुड़े प्रत्याशित आउटपुटों (उदाहरणार्थ रिपोर्ट, आंकड़ा, सर्वेक्षण आदि) भी होंगे।

- (6) सचिव, आयोग का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए प्रस्तावों पर कार्यवाही करने से पूर्व, यह सुनिश्चित करेगा कि परामर्शी की नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान मौजूद है।
- (7) संदर्भ-निबंधन में विहित सेवाओं की परिधि उपलब्ध बजट के अनुरूप होगी।

- (8) आयोग द्वारा संदर्भ-निबंधन का अनुमोदन करने के पश्चात् सचिव परामर्शक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के प्रस्तावों के लिए अनुरोध जारी करेगा या कराएगा तथा ऐसा प्रचार करेगा जैसा आयोग द्वारा समुचित समझा जाए :

परंतु यह कि आयोग सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया ही तैयार करेगा जहां कार्य के लिए संदेय फीस 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

#### 11. प्रस्तावों के लिए अनुरोध

प्रस्तावों के लिए अनुरोध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

- (1) आमंत्रण पत्र, जिसमें परामर्शी सेवाओं के उपबंध के लिए संविदा करने के लिए आयोग का आशय, योजना के ब्यौरों तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तारीख, समय तथा पता होगा।
- (2) परामर्शियों को जानकारी में ऐसी सभी अद्यतन जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्रदान करके तथा मूल्यांकन मानदंडों और कारकों को उपदर्शित करके तथा उनका अपना-अपना महत्व तथा न्यूनतम पूर्व-अर्हता परिधि तथा विशेष अर्हता खंड, यदि कोई हो, उपदर्शित करके अनुकूल प्रस्तावों करने में उनकी सहायता करेगा।
- (3) संदर्भ-निबंधन, जो उपरोक्त विनियम 10(5) में तैयार किए गए हों।

#### 12. प्रस्तावों की प्राप्ति

- (1) आयोग ऐसा समय विहित कर सकेगा जिसके भीतर परामर्शी अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करेंगे।
- (2) आयोग, जहां समुचित समझे, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ा सकेगा।
- (3) समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात तकनीकी या वित्तीय प्रस्तावों के लिए किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रस्ताव सीलबंद कवर में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (5) जहां आयोग यह विहित करता है कि पृथक् तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएं, वहां ये पृथक्तः सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

#### 13. प्रस्तावों का मूल्यांकन

- (1) प्रस्तावों का मूल्यांकन क्वालिटी या लागत, दोनों के आधार पर किया जाएगा।

- (2) प्रस्ताव का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।
- (3) जहां आयोग यह विनिश्चय करता है कि तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन पृथक्तः किया जाए वहां समिति जब तक तकनीकी प्रस्तावों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वित्तीय प्रस्तावों को नहीं खोलेगी।

#### 14. तकनीकी मूल्यांकन

- (1) तकनीकी मूल्यांकन उपरोक्त उप-विनियम (2) में दिए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विनियम 13(2) की अधीन नियुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक मानदंड को 1 से 100 तक के अंक दिए जाएंगे या प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों के औसत तकनीकी रक्कोर को मापा जाएगा। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए भारित औसत तकनीकी रक्कोर की संगणना करने के लिए आयोग के अनुमोदन से समिति द्वारा निम्नलिखित रेंज भार का उपयोग किया जाएगा :-

मानदंड	भार की रेंज
कार्य के लिए परामर्शी का सुसंगत अनुभव	0.10 से 0.40 तक
प्रस्तावित पद्धति की क्वालिटी	0.20 से 0.50 तक
प्रस्तावित प्रमुख कर्मचारिवृंद की अर्हताएं	0.30 से 0.60 तक
आयोग के कर्मचारिवृंद को ज्ञान के अंतरण की सीमा	0.05 से 0.35 तक

टिप्पण : आयोग द्वारा अनुमोदित अधिकतम भार कुल का 1 होगा।

- (3) जहां कार्य प्रमुख कर्मचारिवृंद के कार्य-निष्पादन पर जटिल रूप से निर्भर करता है वहां प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग करते हुए नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित व्यष्टिकों की अर्हताओं पर किया जाएगा :-

  - (क) साधारण अर्हता : साधारण शिक्षा तथा प्रशिक्षण, अनुभव की अवधि, धारित पद, कर्मचारिवृंद के रूप में परामर्शी फर्म के साथ अनुभव, विकसित देशों आदि में अनुभव।
  - (ख) कार्य के लिए पर्याप्तता : विनिर्दिष्ट सेक्टर, क्षेत्र, विषय में शिक्षा, प्रशिक्षण अनुभव तथा विशिष्ट कार्य के लिए सुसंगता।
  - (ग) क्षेत्रीय अनुभव : स्थानीय/प्रशिक्षण स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली, संगठन तथा संरक्षित का ज्ञान।

- (4) तकनीकी मूल्यांकन पूरा करने के पश्चात्, आयोग ऐसे परामर्शियों को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हक अंक को पूरा नहीं करते हैं या निबंधन-संदर्भ के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया हो तथा चयन प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात् उनके वित्तीय प्रस्तावों को बिना खोले वापस करेगा। आयोग को कार्य की प्रकृति तथा अपेक्षा के आधार पर अंकों का वितरण करने का अधिकार होगा।

इसके साथ-साथ ऐसे परामर्शियों, जो न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं, को वित्तीय प्रस्तावों को खोलने के लिए तारीख तथा समय के बारे में सूचित किया जाएगा जिसमें परामर्शियों को खोलने वांछा किए जाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

#### 15. वित्तीय मूल्यांकन

- (1) पूर्व-अर्हित परामर्शियों के वित्तीय प्रस्तावों को समिति द्वारा उन परामर्शियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जिनकी बोलियों की वित्तीय मूल्यांकन के लिए छंटाई की गई है। प्रस्तावित कीमतों को तेज़ आवाज में पढ़ा जाएगा तथा कार्यवाहियों के कार्यवृत्त को अभिलिखित किया जाएगा।
- (2) सचिव पूरे किए जाने वाले वित्तीय प्रस्तावों का पुनर्विलोकन कराएगा। लागत को, एक समान क्रय (विनिमय) दरों का उपयोग करते हुए एकल मुद्रा में संपरिवर्तित किया जाएगा।
- (3) न्यूनतम लागत वाले प्रस्ताव को 100 वित्तीय स्कोर दिया जाएगा और अन्य प्रस्तावों को ऐसा वित्तीय स्कोर दिया जाएगा जो उनकी कीमतों के विपरीत अनुपात में हो।

#### 16. वित्तीय तथा तकनीकी स्कोरों का मूल्यांकन

- (1) वित्तीय तथा तकनीकी स्कोरों को जोड़ते हुए कुल स्कोर अभिप्राप्त किया जाएगा तथा उच्चतर कुल स्कोर वाले परामर्शी को विहित समय-सीमा के भीतर आयोग द्वारा संविदा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वित्तीय स्कोर के लिए अधिमान कार्य की जटिलता तथा क्वालिटी के सुसंगत महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा विहित किया जाएगा। तथापि, किसी भी दशा में, अधिमान कभी भी वित्तीय वर्ष के 0.3 से अधिक नहीं होगा।
- (2) आयोग ऐसे किसी या सभी प्रस्तावों को रद्द कर सकेगा जो प्रतिकूल या अनुपयुक्त पाए जाएं या जो निबंधन-संदर्भ का अनुपालन करने में प्रमुख कमियां पाई जाएं या उनमें सारवान रूप से मूल प्राक्कलन से अधिक लागत अंतर्वर्लित हों।

**17. एकल स्रोत चयन**

आयोग द्वारा ऐसे समुचित मामलों में एकल स्रोत चयन का सहारा लिया जा सकेगा जहां इससे स्पष्ट रूप से फायदा हो क्योंकि कार्य को परामर्शी द्वारा किए गए पूर्व कार्य स्वयं समझा गया हो, या जहां आवश्यक चयन अनिवार्य हो या ऐसे छोटे-छोटे कार्य के लिए, जहां संदेय फीस 5 लाख से अधिक न हो या वहां केवल एक ही फर्म अर्हित अपने-आप किया गया हो या उसके पास कार्य के लिए अनुभव हो।

**18. व्यष्टिक परामर्शियों का चयन**

व्यष्टिक परामर्शियों की नियुक्ति कार्य के लिए उनकी अर्हताओं तथा अनुभव के आधार पर की जाएगी। उनका चयन संदर्भ के आधार या उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जिनका प्रस्ताव आयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो। उनकी उपयुक्तता का निर्णय शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अनुभव तथा यथा समुचित स्थानीय परिस्थिति, प्रशासनिक प्रणाली तथा सरकारी संगठन के ज्ञान के आधार पर किया जाएगा।

**19. हित के प्रतिकूल**

परामर्शी को ऐसा कोई कार्य नहीं दिया जाएगा जो अन्य ग्राहकों के लिए पूर्व या वर्तमान बाध्यताओं के प्रतिकूल हो या उनको ऐसी स्थिति में न रखा गया हो जिसे कार्य को यथार्थ रूप से और निष्पक्ष रूप से करने में समर्थ न हों।

**20. परामर्शियों की नियुक्ति**

नियुक्ति के लिए चयन किए गए परामर्शी से व्यष्टिक मामलों में समुचित रूप से विचार किए गए ऐसे फेरफारों तथा उपांतरणों के साथ इन विनियमों के अंत में दिए गए प्ररूप में करार निष्पादित करने की अपेक्षा की जाएगी।

**21. आयोग की अंतर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति**

इन विनियमों की कोई बात आयोग को ऐसी प्रक्रिया को अपनाने से वर्जित नहीं करेगी, जो इन विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के फेरफार से हुई हो, यदि आयोग, मामले या मामले के वर्ग की विशेष परिस्थितियों की दृष्टि से तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इसे इन विनियमों में विहित प्रक्रिया से अलग रखने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

**22. संशोधन करने की साधारण शक्ति**

आयोग किसी समय तथा ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक समझे, उन उद्देश्यों जिसके लिए इन विनियमों को विरचित किया गया है, को पूरा करने के प्रयोजन के लिए इन विनियमों के किसी उपबंध को संशोधित कर सकेगा।

## 23. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती हैं तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा कोई ऐसी बात कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, या कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

जे. एस. सहरावत, सचिव

[ विज्ञापन III/4/218-I/09-असा.]

### अनुसूची

#### व्यष्टिक परामर्शियों के लिए फीस

प्रवर्ग	प्रति व्यक्ति अधिकतम फीस	दैनिक भत्ता*
सलाहकार	5,000/-रुपए	खाने तथा ठहरने के खर्चों के लिए वास्तविक
वरिष्ठ परामर्शी	4,000/-रुपए	खाने तथा ठहरने के खर्चों के लिए वास्तविक
परामर्शी	2,000/-रुपए	खाने तथा ठहरने के खर्चों के लिए वास्तविक

\* टिप्पण : आयोग मामला-दर-मामला आधार पर दैनिक भत्ता के रूप में अनुज्ञेय लोक रकम को विनिर्दिष्ट करने, उस सीमा जिसके लिए वास्तविक खर्च अनुज्ञात किए जाते हैं, के भीतर युक्तियुक्त सीमा का अवधारण करने तथा उसके लिए प्रस्तुत किसी दावे की युक्तियुक्तता का निर्धारण करने का अधिकार आरक्षित रखता है।

### अनुसूची

अनुच्छेद करार एक पक्षकार (प्रथम) (परामर्शी) तथा दूसरे पक्षकार के रूप में संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आयोग" कहा गया है) के बीच ————— से ————— तक ————— को किया गया।

आयोग ने परामर्शी के रूप में पहले पक्षकार को नियुक्त किया है तथा प्रथम पक्ष का पक्षकार इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट निबंधनों तथा शर्तों पर आयोग को परामर्शी सेवाएं देने के लिए सहमत हो गया है।

अतः ये विलेख इस बात का साक्षी है और पक्षकार क्रमशः निम्नलिखित रूप से सहमत है :

- (1) पहले भाग का पक्षकार (परामर्शी) आयोग या उन अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के आदेशों को स्वयं प्रस्तुत करेगा जिसके अधीन वह आयोग द्वारा समय-समय पर रखा जा सकेगा।

५७७८०/१०-३

- (2) पहले भाग का पक्षकार (परामर्शी) ————— से प्रारंभ होने —————  
— तक की अवधि के भीतर अनुसूची “क” में यथा अंतर्विष्ट कार्य को पूरा  
करेगा।
- (3) पहले भाग (परामर्शी) के पक्षकार को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा।
- (4) संदायों की अनुसूची निम्नानुसार होगी।
- (5) परामर्शी कार्य के संबंध में स्थानीय यात्रा के लिए पहले भाग के पक्षकार को  
कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा (किसी व्यस्तिक कार्य के लिए  
तथ निबंधनों पर निर्भर करते हुए परिवर्तन किया जा सकेगा)।
- (6) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करने के  
पश्चात् आयोग द्वारा फीस का संदाय किया जाएगा।
- (7) गोपनीय प्रकृति की कोई भी जानकारी, जो इस संविदा के विषयवस्तु की  
नियुक्ति के आधार पर परामर्शी या उसके किसी कर्मचारी की जानकारी या  
उसके पास हो, किसी भी रीति से परामर्शी या उसके कर्मचारी या किसी  
अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रकट नहीं की जाएगी। किसी ऐसी कार्रवाई, जो विधि  
के अनुसार आरंभ की जा सकेगी, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस खंड के  
अधीन आयोग को ऐसे प्रतिकर का संदाय करने के दायित्व के लिए परामर्शी के  
अधीन रहते हुए हो सकेगी जैसा आयोग द्वारा प्रकट की गई जानकारी की  
प्रकृति, रीति तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, तथा ऐसे अप्राधिकृत प्रकटन  
द्वारा हुई नुकसानी तक विनिश्चय किया जाए।
- (8) प्रथम भाग का पक्षकार यह वचनबंध करता है कि यह कार्य अन्य ग्राहकों की  
पूर्व या वर्तमान दायित्वों के प्रतिकूल नहीं होगा और न ही निष्पक्ष दृष्टि से तथा  
समदर्शिता से कार्य को करने में स्वयं समर्थ होने की स्थिति में नहीं होगा।
- (9) यथा पूर्वोक्त पक्षकारों के बीच तथा समय-अनुसूची के भीतर कार्य को पूरा करने  
में प्रथम भाग के पक्षकार की ओर से किसी व्यतिक्रम की दशा में, दूसरे भाग  
(आयोग) के पक्षकार को पहले भाग (परामर्शी) के पक्षकार के जोखिम तथा  
लागत पर कार्य को किसी अन्य अभिकरण से पूरा कराने की स्वतंत्रता होगी।
- (10) आयोग को बिना किसी कारण के परामर्शी की नियुक्ति को प्रतिबंधित, बर्खास्त  
या, समाप्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में, प्रथम भाग, (परामर्शी) के  
पक्षकार को, ऐसी नियुक्ति को प्रतिबंधित, बर्खास्त या रद्द करने से पूर्व पूरे किए  
गए कार्य पर विचार करने के पश्चात् ऐसा पारिश्रमिक दिया जाएगा जैसा  
आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए तथा आयोग का विनिश्चय निश्चायक तथा  
आबद्धकर होगा। इस प्रकार नियत तथा संदत्त पारिश्रमिक को ऐसे मामलों में  
अंतिम संदाय समझा जाएगा।
- (11) यदि इस करार के पक्षकारों के बीच कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, तो  
उसे आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया  
जाएगा। कार्यवाहियां समय-समय पर, यथासंशोधित माध्यस्थम् तथा सुलह  
अधिनियम, 1996 के अधीन रहते हुए होगी।

## (12) परामर्शी के कार्मिक

प्रथम भाग (परामर्शी) का पक्षकार नाम, स्थिति तथा अर्हताओं के साथ कार्मिकों का विवरण देगा।

## (13) कार्मिकों का हटाया जाना और/या प्रतिस्थापन

जैसा आयोग अन्यथा सहमत न हो उसके सिवाय, प्रमुख कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि, किसी कारण से, जो परामर्शी के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे हो, किसी प्रमुख कार्मिकों को हटाना आवश्यक हो तो परामर्शी तत्काल उस व्यक्ति के समकक्ष या बेहतर अर्हताओं वाला दूसरा ऐसा व्यक्ति देगा जो आयोग को स्वीकार्य हो।

## (14) यदि आयोग यह पाता है कि यदि कोई कार्मिक (1) गंभीर कदाचार कार्रवाई या दांड़िक कार्रवाई करने के लिए आरोपित किया गया है या (2) किसी कार्मिक के कार्य-निष्पादन से असंतुष्ट होने का युक्तियुक्त कारण है, तब परामर्शी, सचिव के लिखित अनुरोध पर, उसके लिए कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, तत्काल ऐसे दूसरे व्यक्ति को देगा जिसकी अर्हता तथा अनुभव आयोग को स्वीकार्य हो। परामर्शी कार्मिकों को हटाने और/या उनको बदलने से उद्भूत या आनुषंगिक किसी अतिरिक्त लागत का कोई दावा नहीं करेगा।

## (15) पहले भाग (परामर्शी) का पक्षकार का नोडल व्यक्ति श्री -----

## (16) आयोग की ओर सचिव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग नोडल अधिकारी होगा।

## (17) कोई अन्य निबंधन तथा शर्तें।

## (18) किसी ऐसे मामले की बाबत जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, परामर्शियों की नियुक्ति के अधीन रहते हुए, भारत सरकार के साधारण अनुदेशों में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे।

इस साक्ष्यस्वरूप प्रथम भाग के पक्षकार (परामर्शी) और आयोग की ओर से आयोग के - -----ने उपरोक्त लिखित दिन तथा वर्ष के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

प्रथम भाग के पक्षकार ने -----की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

आयोग तथा आयोग की ओर से -----की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
(For the State of Goa and Union Territories)**

**NOTIFICATION**

Gurgaon, the 11th February, 2010

**No. JERC-8/2009.—**

In exercise of powers conferred on it by Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations, namely:

**1. Short title and commencement**

- (1) These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2009.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions. —**

- (1) In these regulations unless the context otherwise requires: -
  - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
  - (b) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories;
  - (c) "Consultant" includes any individual - not in the employment of the Commission, firm, body or association of persons, who or which possesses or has access to any specialized knowledge, experience or skill;
  - (d) "Secretary" means the Secretary of the Commission.
- (2) Words or expressions occurring in these regulations and not defined herein but defined in the Act or in the Joint Electricity regulatory Commission (Conduct of Business) regulations, 2009 shall bear the same meaning as in the Act or in the said Conduct of Business Regulations.

### **3. Scope of Work**

The Commission may from time to time appoint consultants for executing specialized tasks for which skills are either not available within the staff of the Commission or where the nature of job is specific and time-bound or where the Commission considers appointment of consultant to be conducive or more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, cost, time or on any other consideration.

- (1) The terms and conditions of engagement of consultants will be drawn up in each case and agreed to between the consultant and the commission prior to award of consultancy.
- (2) The terms of engagement would specify the exact nature of the tasks to be undertaken by the consultant, the time allowed for completion of each task and the specific outputs that are to be provided by the consultant in relation to each work.

### **4. Period of Appointment**

The consultant shall be appointed for the minimum period:

Provided that the period of initial appointment of a consultant on any specific assignment shall not normally exceed two years:

Provided further that period of appointment may be extended subject to the condition that the maximum period of continuous appointment of a consultant in no case shall exceed four years.

### **5. Categorisation of Consultants**

The consultants shall be categorized as: (a) Institutional consultants, and (b) Individual consultants.

### **6. Institutional Consultant**

Institutional consultant may be appointed where the Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which, in its opinion, may be more appropriately provided by a firm, or a company or an association or body of persons.

### **7. Individual Consultant**

Individual consultant may be appointed for assignments for which teams of personnel are not required, where the experience and qualifications of the individual are of paramount consideration and the Commission is of the opinion that the consultancy services can be more efficiently performed by an individual, having regard to the qualifications and experience considered relevant for the assignment.

57746710-4

## **8. Categorization of Individual Consultants**

(1) Based on experience, individual consultants shall be categorized as

<b>Category</b>	<b>Minimum Experience in the Area of Appointment</b>
Advisors	15 years
Senior Consultants	10 years
Consultants	3 years

- (2) The Commission may prescribe minimum educational qualifications, depending on the nature of the work, and the relevant professional qualifications related to subject area of the consultancy.
- (3) The Commission may in appropriate case, for reasons to be recorded in writing, relax the educational qualifications, keeping in view the overall expertise of the person being considered for engagement as individual Consultant.

## **9. Fees and Other Charges in Case of Individual Consultants**

(1) Except where the Commission directs otherwise, the individual consultant shall be appointed generally on a consolidated fee at the rates specified in the Schedule.

Provided that the Commission may from time to time by an order in writing, direct revision of the rates of fee specified in the Schedule.

(2) No payments in addition to the consolidated fee in accordance with sub-regulation (1) shall be made in the case of individual consultant:

Provided that the Commission may allow an additional amount not exceeding 10% of the fee payable to the consultant to cover expenditure of contingent nature.

(3) Where the consultant has to incur expenditure on travel to and stay at a place away from the headquarters of the Commission, the Commission shall reimburse the cost of travel by an appropriate class, not lower than that permitted to a Group A Officer of the Central Government and authorize payment of Daily Allowance, as specified in the schedule, in addition to fee and other charges payable under these regulations, for such number of days as the Commission may consider appropriate.

(4) The fee and other charges payable to individual consultants under these regulations shall also be payable to former and retired Government servants appointed as consultants.

(5) In the case of an institutional consultant the rates for different categories of individual consultants will be used as a broad guide line to determine the reasonableness of costs

allocated to consultant time in the proposal. In addition to the costs for consultant time, amount allowable for overheads on account of office expenditure like telephone, photocopying, fax expenses etc. will be subject to negotiation and broadly be based on actual position regarding these expenditures. The limit for contingency in the case of Institutional consultant will be 10% of the fees payable for consultant time besides the amount allowed as overhead for office expenses.

## 10. Appointment of Consultant

- (1) The Commission, on being satisfied that there is a need to avail services of the consultant for any task, shall direct the Secretary to prepare or cause to be prepared the details terms of reference.
- (2) The Commission may decide either to invite combined technical and financial proposals or separate technical and financial proposals.
- (3) The Commission may prescribe the minimum qualifying marks for the technical bid.
- (4) The Secretary shall prepare or cause to be prepared the detailed terms of reference for the appointment of consultant for any specific task and shall obtain approval of the Commission.
- (5). The terms of reference shall be prepared to specify the objectives, goals and scope of the assignment and provide background information including a list of existing relevant studies and basic data to facilitate the consultant in preparation of his proposal:

Provided that the terms of reference shall also list the services and surveys necessary to carry out the assignment and the expected outputs (for example reports, data, surveys etc.) linked to each task included in the terms of reference.

Provided further that where transfer of knowledge, training is an objective, the terms of reference shall detail the number of staff to be trained.

- (6) The Secretary prior to processing the proposal for obtaining approval of the Commission shall ensure that the necessary budgetary provisions exist for the proposal to appoint consultant.
- (7) The scope of the services described in the TOR shall be compatible with the available budget.
- (8) After approval of the terms of reference by the Commission, the Secretary shall issue or cause to be issued the request for proposals to invite proposals for appointment as

consultant and give such publicity as may be considered appropriate by the Commission  
Provided that the Commission may dispense with the process of issuing public advertisement where the fee payable for an assignment does not exceed Rs.5 lakhs.

## 11. Request for proposals

The request for proposals shall include the following:-

- (1) A letter of invitation stating the intention of the Commission to enter into a contract for provision of consultancy services, the details of the plan and the date, time and address for submission of proposals.
- (2) Information to the consultants shall contain all necessary information that will help them to prepare responsive proposals by providing information on the evaluation process and by indicating the evaluation criteria and factors and their respective weights and the minimum pre-qualification score and special qualifying clause if any.
- (3) Terms of reference as prepared in regulation 10 (5) above.

## 12. Receipt of proposals

- (1) The Commission shall prescribe the time within which the consultants shall submit their proposals.
- (2) The Commission may where considered appropriate extend the time limit for submission of proposals.
- (3) No amendment to the technical or financial proposals shall be accepted after expiry of the time limit.
- (4) The proposals shall be submitted in sealed cover.
- (5) Where the Commission prescribes that separate technical and financial proposals be submitted, they shall be submitted in separate sealed envelopes.

## 13. Evaluation of proposals

- (1) The proposal shall be evaluated both on the basis of quality as well as cost.
- (2) The proposal shall be evaluated by a Committee appointed by the Commission.
- (3) Where the Commission decides that the technical and financial proposals be evaluated separately, the Committee shall not have access to the financial proposals, until evaluation of the technical proposals is completed.

#### **14. Technical Evaluation**

- (1) Technical evaluation will be done by the Committee appointed under regulation 13(2) above taking into account the criteria given under sub-regulation (2) below.
- (2) Each criterion shall be marked on a scale of 1 to 100 and then the marks for each criterion shall be weighted to become average technical scores. Weights in the following ranges will be used by the Committee, with the approval of the Commission, to calculate the weighted average technical score for each proposal:-

Criterion	Range of Weights
Consultant's relevant experience for the assignment	0.10 to 0.40
Quality of the methodology proposed	0.20 to 0.50
Qualifications of the key staff proposed	0.30 to 0.60
Extent of transfer of knowledge to the staff of the Commission	0.05 to 0.35

Note: The mix of weights approved by the Commission will total to 1.

- (3) Where the assignment depends critically on the performance of the key staff, the proposal shall be evaluated on the qualifications of the individuals proposed to be appointed using the following criteria: -
- (a) General qualifications: General education and training, length of experience, positions held, time with the consulting firm as staff, experience in developing countries etc.
  - (b) Adequacy for the assignment: Education, training, experience in the specific sector, field, subject and relevance to the particular assignment.
  - (c) Regional Experience: knowledge of the administrative system, organization and culture at the local / regional level.
- (4) After the technical evaluation is completed the Commission shall inform those Consultants whose proposals did not meet the minimum qualifying mark or were considered non-responsive to the terms of reference, and their financial proposals will be returned unopened after completing the selection process. The Commission shall have the right of distribution of marks on the basis of nature and requirement of the assignment.

577 6010-5

Simultaneously, those Consultants who have secured the minimum qualifying marks shall be informed about the date and time for

opening the financial proposals, giving sufficient time for the Consultants to be present at the opening should they so desire.

## **15. Financial Evaluation**

- (1) The financial proposals of the pre-qualified Consultants will be opened by the committee in the presence of consultants or their representatives whose bids are shortlisted for financial evaluation. The proposed prices shall be read aloud and recorded in minutes of the proceedings.
- (2) The Secretary will cause a review of the financial proposals to be done. The cost will be converted to a single currency using uniform selling (exchange) rates.
- (3) The proposal with lowest cost will be given a financial score of 100 and other proposals given financial scores that are inversely proportional to their prices.

## **16. Evaluation of financial and technical scores**

- (1) The total score shall be obtained by weighting the technical and financial scores and adding them and the consultant with highest total score shall be invited by the Commission to enter into a contract within the prescribed time limit. The weight for the financial score shall be as prescribed by the Commission in each case taking into account the complexity of the assignment and the relative importance of quality. However, the weight will never exceed 0.3 for the financial score in any case.
- (2) The Commission may reject any or all proposals if they are found to be unresponsive or unsuitable either because they represent major deficiencies in complying with the terms of reference or they involve cost substantively higher than the original estimate.

## **17. Single source selection**

Single source selection may be resorted to by the Commission in appropriate cases where it represents a clear advantage because the tasks represent a natural continuation of previous work carried out by the consultant, or where an urgent selection is essential, or for small assignment where the fee payable does not exceed Rs. 5 lakhs or where only one firm is qualified or has experience for the assignment.

## **18. Selection of individual Consultants**

Individual consultants may be selected on the basis of their qualifications and experience for the assignment. They may be selected on the basis of references or from amongst those who are approached directly by the Commission. Their suitability shall be judged on the basis of

academic background, experience and, as appropriate, knowledge of local conditions, administrative system and government organization.

### **19. Conflict of interest**

Consultant shall not be hired for any assignment that would be in conflict with his prior or current obligations to other clients or that may place them in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.

### **20. Appointment of Consultants**

The consultant selected for appointment shall be required to execute an agreement in the format given at the end of these regulations, with such variations and modifications considered appropriate in individual cases.

### **21. Saving of inherent power of the Commission**

Nothing in these provisions shall bar the Commission from adopting a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure prescribed in these Regulations.

### **22. General power to amend**

The Commission may at any time and on such terms, as it may think fit, amend any provision of these Regulations for the purpose of meeting the objectives with which these Regulations have been framed.

### **23. Power to remove difficulties**

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

J. S. SEHRAWAT, Secy.  
[ADVT III/4/218-I/09-Exty.]

577 40/10-5

## SCHEDEULE

Fee for Individual Consultants

<b>Category</b>	<b>Maximum Fee per man-day</b>	<b>Daily Allowance*</b>
Advisors	Rs. 5000	Actual for boarding and lodging expenses
Senior Consultants	Rs. 4,000/-	Actual for boarding and lodging expenses
Consultants	Rs. 2,000/-	Actual for boarding and lodging expenses

\* Note: The Commission reserves the right to specify the exact amounts permissible as daily Allowance, determine the reasonable limits within which actual expenses are to be allowed, on a case-to-case basis, and assess the reasonableness of any claim submitted thereof.

## SCHEDEULE

Articles of Agreement made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ of one (first) part (Consultant) and the Joint Electricity Regulatory Commission (herein after called "the Commission") of the other (Second) part.

Whereas the Commission has engaged the party of the first part as a Consultant and the party of the first part has agreed, to provide the consultancy services to the Commission, on the terms and conditions herein after contained.

Now these presents witness and the parties hereto respectively agree as follows:

- 1) The party of the first part (Consultant) shall submit himself to the orders of the Commission and of the officers and authorities under whom he may from time to time be placed by the Commission.

- 2) The party of the first part (Consultant) shall complete the assignment as contained in Schedule – ‘A’ within a period of \_\_\_\_\_ commencing from \_\_\_\_\_
- 3) The party of the first part (Consultant) shall be paid as under
- 4) The schedule of payments shall be as under
- 5) No TA/DA shall be admissible to the party of the first part for local journeys in connection with the consultancy assignment. (may be varied depending on terms agreed for any individual assignment)
- 6) The payment of fee shall be made by the Commission after the deduction of tax at source in accordance with law for the time being in force.
- 7) Any information of confidential nature, which comes to the knowledge or into the possession of the consultant or of any its employees by virtue of the engagement subject matter of this contract shall not be disclosed by the consultant or its employees to any unauthorized person in any manner. Any breach of this clause without prejudice to any other action that may be initiated according to law, shall also subject the consultant to a liability to pay to the Commission such compensation as may be decided by the Commission keeping in view the nature, manner and motive of the information disclosed and the extent of the damage caused by such unauthorized disclosure.
- 8) The party of the first part undertakes that this assignment shall not be in conflict with its prior or current obligation to other clients nor shall it place itself in a position of not being able to carry out the assignments objectively and impartially.
- 9) In case of any default on the part of the party of the first part in completion of the work within time schedule agreed to between the parties as herein above, the party of the second part (the Commission) shall be at liberty to get the work completed from any other agency at the risk and cost of the party of the first part (Consultant).
- 10) The Commission reserves its right to foreclose, terminate or cancel the engagement of the consultant without assigning any reasons. In such cases party of the first part (Consultant) shall be paid remuneration after taking into consideration the portion of work completed prior to such foreclosure, termination or cancelation of the engagement as may be decided by the Commission and the decision of the Commission shall be conclusive and binding. The remuneration so fixed and paid shall be deemed to be the final payment in such cases.
- 11) In case of any differences or disputes between the parties arising out of this AGREEMENT, the same shall be referred for arbitration of a person nominated by the Commission. The proceedings shall be subject to the Arbitration and Conciliation Act 1996, as amended from time to time.

12) Consultant's Personnel

The party of the first part (Consultant) shall provide Description of personnel with names, position and qualifications.

13) Removal and/or replacement of the personnel

Except as the Commission may otherwise agree, no change shall be made in the key personnel. If, for any reason, beyond the reasonable control of the Consultant, it becomes necessary any of the key personnel, the Consultant shall forthwith provide as a replacement a person of equivalent or better qualifications, which is acceptable to the Commission.

14) If the Commission finds that any of the personnel (1) committed serious misconduct or has been charged with having committed a criminal action or (2) have reasonable cause to be dissatisfied with the performance of any of the personnel, then the Consultant shall, at the Secretary's written request, specifying the ground therefore, forthwith provides as a replacement a person with qualification and experience acceptable to the Commission. The Consultant shall have no claim for additional costs arising out of or incidental to any removable and /or replacement of personnel.

15) Nodal Person of the party of the first part (Consultant) Mr. \_\_\_\_\_

16) The Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission, shall be the Nodal Officer on behalf of the Commission.

17) Any other terms and conditions

18) In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement, the provisions contained in the general instructions of the Government of India on the subject of engagement of consultants shall apply.

IN WITNESS WHERE OF the party of the first part (Consultant) and \_\_\_\_\_ to the Commission on behalf of the Commission have hereto put their hands on the day and the year first above written.

Signed by \_\_\_\_\_ the party of the first part in the presence of \_\_\_\_\_

Signed by \_\_\_\_\_ to the Commission for and on behalf of the Commission in the presence of \_\_\_\_\_